

अंतर्गत न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम सह विशेष न्यायाधीश।
वैशाली, हाजीपुर।

आपराधिक पुनरीक्षण वाद सं०-230/2025.

परिवाद पत्र सं०-2270/2024

1. पूजा कुमारी आवेदिका।

बनाम

- (1) बिहार सरकार
- (2) सुधीर सिंह
- (3) श्री राम सिंह.....
- (4) धर्मशीला देवी
- (5) मिथिलेस कुमार.....
- (6) संध्या कुमारी उर्फ रेखा विपक्षीगण।

आदेश

13.05.2026

प्रस्तुत आपराधिक पुनरीक्षण वाद श्रीमती हरिप्रिया, न्यायिक दण्डाधिकारी-प्रथम श्रेणी, वैशाली, हाजीपुर के द्वारा पारित आदेश दिनांक-06/07-11-2025 के विरुद्ध दाखिल की गयी है। पारित आदेश दिनांक-06/07-11-2025 में तत्कालीन न्यायिक दण्डाधिकारी-प्रथम श्रेणी, वैशाली द्वारा वाद में उभय पक्षों के सुनवाई के पश्चात् केवल विपक्षी सं०-2 सुधीर सिंह के विरुद्ध धारा 323 भा.द.वि. के अंतर्गत संज्ञान लिया गया है।

प्रस्तुत आपराधिक पुनरीक्षण वाद में विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि पुनरीक्षणकर्ता/आवेदिका द्वारा आज के पूर्व इस न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में कोई आवेदन उपरोक्त संदर्भ में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदिका, विपक्षी सं०-2 का पत्नी है जिसका विवाह हिंदु रिति रिवाज के अनुसार हुयी थी तथा उपहार स्वरूप समान भी दिया गया था। विवाह पश्चात् आवेदिका विदाई होकर अपने ससुराल गयी जहां पर दोनों पति-पत्नी खुशीपूर्वक साथ में रह रहे थे लेकिन कुछ समय बाद आवेदिका को प्रताड़ित किया जाने लगा और दहेज के रूप में विपक्षीगण द्वारा 05 लाख रुपये की मांग किया जाने लगा जिसकी पूर्ति नहीं होने पर आवेदिका का स्त्रीधन छीनकर उसे घर से निकाल दिया गया उसके बाद आवेदिका अपने मायके माता-पिता के पास रहने लगी। विपक्षी सं०-2, 3, 4, 5 एवं 6 के व्यवहार से तंग आकर आवेदिका द्वारा तत्कालीन मुख्य

अंतर्गत न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम सह विशेष न्यायाधीश।
वैशाली, हाजीपुर।

आपराधिक पुनरीक्षण वाद सं०-230/2025.

न्यायिक दण्डाधिकारी, वैशाली के न्यायालय में परिवाद पत्र 2270/2024 दाखिल किया गया था, जिसे तत्कालीन मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, वैशाली द्वारा श्रीमति हरिप्रिया, न्यायिक दण्डाधिकारी-प्रथम श्रेणी, वैशाली के यहां स्थानांतरित किया गया जहां पर आवेदिका एवं अन्य द्वारा परिवाद पत्र का पूर्ण समर्थन किया गया इसके बावजूद माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक-06/07-11/2025 में परिवाद पत्र को विपक्षी सं०-3 से 5 के विरुद्ध खारिज किया गया तथा केवल विपक्षी सं०-2 सुधीर सिंह के विरुद्ध धारा 323 भा.द.वि. के अंतर्गत संज्ञान लिया गया है। तत्कालीन न्यायिक दण्डाधिकारी-प्रथम श्रेणी का आदेश पूर्ण अवैध और साक्ष्य के विपरीत है। आगे विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि तत्कालीन न्यायिक दण्डाधिकारी-प्रथम श्रेणी, वैशाली के आदेश दिनांक- 06/07-11/2025 को खारिज किया जाए।

विपक्षी सं०-1 की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक उपस्थित है और उक्त आवेदन का विरोध करते हैं तथा विपक्षीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि तत्कालीन न्यायिक दण्डाधिकारी-प्रथम श्रेणी, वैशाली का आदेश दिनांक 06/07-11/2025 वैधानिक एवं संपुष्ट करने योग्य है। माननीय न्यायालय द्वारा साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुये आदेश पारित किया गया है। आगे अनुरोध किया गया कि प्रस्तुत आपराधिक पुनरीक्षण वाद खारिज किया जाए।

प्रस्तुत आपराधिक पुनरीक्षण वाद में उभय पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि पुनरीक्षणकर्ता का मुख्य विरोध इस तथ्य पर है कि अवर न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार का दुरुपयोग किया है क्योंकि वह किसी भी विवाह को शुन्य घोषित करने का क्षेत्राधिकार नहीं रखती है क्योंकि यह क्षेत्राधिकार प्रधान न्यायाधीश का है। पुनरीक्षणकर्ता अपने आवेदन के कंडिका 2 में वर्तमान में भी विपक्षी सं०-2 सुधीर सिंह की वैध विवाहिता पत्नी होने का दावा कर रही है। पुनरीक्षणकर्ता का निवेदन है कि चूंकि वह विपक्षी सं०-2 सुधीर सिंह की विवाहिता पत्नी है इसलिए उनके विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 498ए, में संज्ञान लेने से मना करने का कोई विधिक आधार नहीं है। यह बात सत्य है कि अवर न्यायालय को किसी विवाह को शुन्य या शुन्यकरणीय घोषित करने का

अंतर्गत न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश—प्रथम सह विशेष न्यायाधीश।
वैशाली, हाजीपुर।

आपराधिक पुनरीक्षण वाद सं०-230/2025.

अधिकार नहीं है या किसी विवाह की वैधता निर्धारित करने का अधिकार नहीं है परंतु भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498ए का शीर्षक ही यह है— किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना। यहां पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498ए में आरोपित करने के उद्देश्य से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 204 के अधीन आदेशिका जारी करने के लिए प्रथमतः यह निश्चित करना होगा कि सूचिका एवं आरोपित के मध्य वैध पति-पत्नी का रिश्ता पूर्व में विद्यमान था। यहां पर पुनरीक्षणकर्ता ने विपक्षी के इस तथ्य से कहीं इंकार नहीं किया है कि वह विपक्षी सं०-2 सुधीर सिंह से विवाह के समय पूर्व से ही एक ऐसे विवाह बंधन में थी जिसमें कि उस समय तक विवाह विच्छेद नहीं हुआ था। हिंदु विवाह अधिनियम की धारा 5 में भी विवाह के आवश्यक शर्तों में यह महत्वपूर्ण शर्त है कि विवाह के दोनों पक्षकार पूर्व से किसी वैवाहिक संबंध के अस्तित्व में नहीं हैं। यहां पर यह निर्धारित करने का आशय यह नहीं है कि यह न्यायालय विवाह की वैधता या अवैधता को निर्धारित कर रहा है बल्कि वह इस तथ्य को निर्धारित कर रहा है कि क्या सूचिका वास्तव में विपक्षी सं०-2 की वैध पत्नी थी क्योंकि बिना पति-पत्नी के रिश्ता को निर्धारित किए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498ए के अधीन आरोप का निर्माण हो ही नहीं सकता है और इसी तथ्य को न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, वैशाली हाजीपुर श्रीमति हरिप्रिया ने अपने आदेश दिनांक 06/07-11-2025 को आधार बनाया है। यहां पर भले ही न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, वैशाली हाजीपुर श्रीमति हरिप्रिया ने यह तथ्य अंकित किया है कि दोनों के मध्य विवाह शुन्य था फिर भी इस निष्कर्ष का अभिप्राय या विधिक महत्व यह नहीं है कि वह ऐसा आदेश करते समय विवाह को शुन्य घोषित की और यदि ऐसा वह करती भी तो यह उनके क्षेत्राधिकार में नहीं था इसलिए वह केवल एक निष्प्राण शब्द ही है। यहां पर संज्ञान आदेश में सिर्फ यह विधिक महत्व का प्रश्न है कि संज्ञान भा.द.वि. की उचित धाराओं में लिया गया है अथवा नहीं तो यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को दुष्टिगत रखते हुए न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, वैशाली हाजीपुर श्रीमति हरिप्रिया ने भा.द.वि. की धारा 498ए में संज्ञान न लेकर कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की हैं और

अंतर्गत न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम सह विशेष न्यायाधीश।
वैशाली, हाजीपुर।

आपराधिक पुनरीक्षण वाद सं०-230/2025.

उन्होंने अपने संज्ञान आदेश के आधारों को भी विस्तृत रूप से स्पष्ट भी किया हैं।
अतः प्रस्तुत आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन अस्वीकृत किया जाता हैं।

लेखापित

(मनोज कुमार तिवारी)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम
सह विशेष न्यायाधीश।
वैशाली, हाजीपुर।



अंतर्गत न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम सह विशेष न्यायाधीश।
वैशाली, हाजीपुर।

आपराधिक पुनरीक्षण वाद सं०-230/2025.

Date of Judgment/Order	13-05-2026
Date of Reserving Judgment/Order	28-04-2026
Uploading Date	15-05-2026
Uploaded by	Pankaj Kumar, D.W.T.C., Vaishali.